175
24/3/2001

पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

22 MAR 2001

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

टर्न-I/22.3.2001/
श्रीरमण/

(11)

द्वादश विधान-सभा
पंचम सत्र

22 मार्च, 2001 ई0
वृहस्पतिवार, तिथि----------
01 चैत्र, 1923 श0

॥ कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न॥

॥ इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया॥

॥व्यवधान॥

अध्यक्ष॥खड़े होकर॥: यह जितना सब है आप उठाईये, जीरो आवर में । आप॥श्री श्रीभगवान सिंह॥आप बैठिये । जितनी बातें हैं जीरो आवर में निकालेंगे ।

॥व्यवधान॥

जीरो आवर में उठायेंगे । हम अनुमति देंगे । अभी कुछ नहीं । अभी कोई बात न सुनी जायेगी, न लिखी जायेगी । हाऊस को चलने दीजिये । जीरो आवर में उठाने की अनुमति देंगे । कुछ नहीं ।

श्री सुशील कुमार मोदी॥नेता विरोधी दल॥: अध्यक्ष महोदय, अनेक महत्त्वपूर्ण सवाल हैं । सिवान का भी मामला है । मेरा आग्रह है कि 12 बजे इसको उठवा देंगे और सरकार का वक्तव्य हो जाये इस पर ।

प्रश्नोत्तर काल ।

॥व्यवधान॥

अध्यक्ष: मैं समता पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कृपया बैठ जांय। जीरो आवर में उठावें ।

॥इस अवसर पर समता पार्टी के कुछ मा0 सदस्यगण सभा-वेश्म में चले आये॥

माननीय सदस्य, श्रीभगवान सिंह । आप अपने स्थान पर चले जांय। मैं 12 बजे लूँगा ।

आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जांय । बोलिये माननीया मंत्री ।

॥व्यवधान॥

माननीय विपक्ष के नेता, श्री मोदीजी, आपसे आग्रह है कि इन्हें अपनी सीट पर बैठाईये ।

॥व्यवधान॥

12 बजे बोलेंगे । कहीं किसी तरह की बात न लिखी जायेगी, न प्रकाशित होगी, जो इन माननीय सदस्यों के द्वारा कही जा रही है ।

(इस अवसर पर मा0 सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर गये)

तारांकित प्रश्न संख्या-११४०

श्री रमई राम(मंत्री): १- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

२- राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय अधिसूचना संख्या-१४२९ (रा०)/दिनांक ३०-१२-२०००/ द्वारा रघुनाथ चौधरी को अंचलाधिकारी फुलपरास, मधुबनी के रुप में पदस्थापित किया गया है । चुनाव के बाद योगदान करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-११४१

श्री रमई राम(मंत्री): १- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

२- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के प्रतिवेदन के अनुसार ९ ऐसे मामले लंबित हैं, विशेष जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

३- सरकार लंबित बकास जमीन की वापसी हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या ४२७ दिनांक १२-३-२००१ द्वारा श्री सतीश प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुपौल को कोशी एरिया की धारा २(I) के अंतर्गत समाहर्त्ता की शक्ति प्रदान की गयी है ताकि बकाये संबंधी सभी लंबित मामले का निष्पादन किया जा सके ।

तारांकित प्रश्न संख्या-११४२ : प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-११४३

श्री शिवशंकर यादव(राज्यमंत्री): १- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष १९९३ में या उसके बाद अभी तक सरकार द्वारा दियारा विकास बोर्ड का गठन नहीं किया गया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दियारा विकास योजना के अंतर्गत वर्ष १९९९-२००० में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा कृषि कर्मियों द्वारा भोजपुर एवं बक्सर जिले में क्रमशः ७ तथा ३ कृषक गोष्ठी सह प्रशिक्षण का आयोजन कियागया, जिसमें कुल २५१ कृषकों को नये कृषि तकनीकी की जानकारी दी गयी । इसके साथ ही भोजपुर जिले में कृषकों के खेतोंपर १० तकनीकी प्रत्यक्षण कराये गये हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि भारत सरकार ने दियारा विकास के लिये वर्ष २००० में

७ करोड़ रुपया राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था । यदि हां तो उस राशि का क्या उपयोग इन कामों के लिये किया गया ?

श्री शिवशंकर यादव(राज्यमंत्री): महोदय, इसमें यह कहां है ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने पूछा है कि दियारा विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया था उसमें भोजपुर तथा बक्सर में दियारा क्षेत्र में विकास के कौन कौन कार्य किये गये हैं । यह भोजपुर और बक्सर दोनों जिला के दियारा क्षेत्र से संबंधित है । इसमें यह प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है कि भारत सरकार से जो ७ करोड़ रु० की राशि आयी थी उसमें इन दोनों जिलोंमें जो व्यय करना था वह हुआ कि नहीं ?

श्री शिवशंकर यादव(राज्यमंत्री): महोदय, मैं एक्ट बता रहा हूं । ९३ से आज तक जो ट्रेनिंग की व्यवस्था थी कि किसानों को ट्रेनिंग देंगे....

अध्यक्ष: नहीं । मंत्री जी इसका जवाब आप अगली तिथि को देंगे । इस पूरक के साथ क्या केन्द्र सरकार की ओर से दियारा विकास के लिये गत वित्तीय वर्ष में ७ करोड़ की राशि विमुक्त की गयी थी ? इसी क्रम में यह भी जवाब देंगे कि भोजपुर और बक्सर में कितना खर्च हुआ ? इसी पूरक के साथ यह प्रश्न स्थगित हुआ ।

श्री कृष्णचंद्र प्रतापसिंह: अध्यक्ष महोदय, दशम वित्तआयोग से भी दियारा विकास के लिये २१ करोड़ रुपया आया था ।

अध्यक्ष: दशम वित्त आयोग से २१ करोड़ रुपया आया था , इस बिंदु को भी माननीय मंत्री देख लेंगे । मंत्री जी अगली तिथि को